10.08.2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

भारतीय जोखिम आधारित पूँजी (इण्ड-आरबीसी) तंत्र की ओर कदम

Move towards Indian Risk Based Capital (Ind-RBC) Framework

मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन -1

Quantitative Impact Study -1

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अपनी विकास-संबंधी कार्यसूची के अंग के रूप में भारतीय बीमा उद्योग के लिए भारतीय जोखिम-आधारित पूँजी (इण्ड-आरबीसी) तंत्र के विकास और कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है। यह तंत्र एक निर्णायक तंत्र के रूप में काम करेगा, जो कि बीमाकर्ताओं को उनकी बीमा और पुनर्बीमा परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों के अनुरूप पूँजी के उचित स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार, वह बीमाकर्ताओं के लिए, पूँजी उपयोग अनुकूलन और उसके कुशल जोखिम प्रबंधन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।

वर्तमान, कारक-आधारित मॉडल से आरबीसी की दिशा में संक्रमण की ओर एक महत्वपर्ण कदम के रूप में, आईआरडीएआई ने `प्रथम मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन' (क्यूआईएस-1) की शुरुआत की है। यह अध्ययन सर्वोपरि महत्व रखता है, क्योंकि यह बीमाकर्ताओं की पूँजी और समग्र शोधनक्षमता पर संभावित प्रभाव के व्यापक मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। एक "तकनीकी मार्गदर्शन" दस्तावेज भी जारी किया गया है, जिसको क्यूआईएस 1 में जोखिमों के परिमाणीकरण और आंकलन में बीमा उद्योग का मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक अभिकल्पित किया गया है। इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है।

सुव्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ताओं को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्यूआईएस1 के परिणामों की प्रस्तुति करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। क्यूआईएस1 के जाँच-परिणामों के मूल्यांकन के उपरांत आईआरडीएआई का विचार क्रमिक मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस), एक गतिशील अनुक्रम का आरंभ करना है, जिसकी परिणति आरबीसी की फाइन-ट्यूनिंग और विकास में हो सकती है और अन्ततः इसका निर्णायक कार्यान्वयन किया जा सकेगा ।

संक्षेप में, आईआरडीएआई का रणनीतिक प्रक्षेप-पथ, बीमा परिदृश्य के भीतर एक सुदृढ और जाँचे-परखे जोखिम-पूँजी सहजीवन को प्रोत्साहित करने वाली सुदृढ प्रतिबद्धता को समाहित करता है। इस कार्य प्रणाली को विवेकपूर्ण दूरदर्शिता के साथ संचालित करके उद्योग 2047 तक न केवल वित्तीय लचीलेपन की ऊँचाइयाँ, बल्कि समावेशी बीमा की सामूहिक दृष्टि भी हासिल करने के लिए तैयार है।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is actively working towards the development and implementation of the Indian Risk-Based Capital (Ind-RBC) Framework for the Indian Insurance Industry as part of its developmental agenda. This framework would serve as a pivotal mechanism which would enable insurers to maintain an appropriate level of capital commensurate with

the risks inherent in their insurance and reinsurance operations. Thus, it would act as a catalyst for insurers in optimizing capital utilization and ensuring efficient risk management.

As a major step towards transition to RBC from the present factor-based model, IRDAI has initiated the First Quantitative Impact Study (QIS1). This study holds paramount significance, as it provides the opportunity to comprehensively evaluate the potential impact on the capital and overall solvency of the insurers. A 'Technical Guidance' document has also been released which is meticulously designed to guide and facilitate the insurance industry in quantification and assessment of risks in the QIS1. A circular has been issued in this regard.

To ensure a streamlined progression, insurers are entrusted with the responsibility of submitting the outcomes of the QIS1 within a prescribed timeframe. Subsequent to the evaluation of the QIS1 findings, the IRDAI envisions embarking on successive Quantitative Impact Studies (QIS), a dynamic sequence that may culminate in the fine-tuning and evolution of the RBC Framework, ultimately resulting in its definitive implementation.

In essence, the IRDAI's strategic trajectory encapsulates a resolute commitment to fostering a robust and well-calibrated risk-capital symbiosis within the insurance landscape. By navigating this course with judicious foresight, the industry is poised to achieve not only heightened financial resilience but also the collective vision of inclusive insurance by 2047.

***